3 नौ देवियों की चैतन्य झांकी का भव्य आयोजन

5 डॉ. हेडगेवार: राष्ट्र चेतना के प्रखर प्रेरणास्रोत

6 डॉ. लोहिया की प्रासंगिकता: रघु ठाकुर का लेख

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

# जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 47 | प्रति सोमवार, 30 मार्च 2026 | मूल्य : दो रुपये | पृष्ठ : 8

## छिंदवाड़ा में भीषण सड़क हादसा

# जबरन भीड़ जुटाने के चक्कर में अनाथ हुए बच्चों का जिम्मेदार कौन?

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

हाल ही में छिंदवाड़ा की दर्दनाक बस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत और 41 घायल होने से कई परिवार उजड़ गए। ये सभी लोग एक सरकारी कार्यक्रम से लौट रहे थे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिरकत की थी। मतलब साफ है भीड़ को तो इकट्ठा करना ही था। भले ही यह भीड़ जबरन लायी गई हो। स्थानीय प्रशासन और स्थानीय राजनेता पूरी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग एकत्रित हों। इसके लिए लोगों को भय, डर और प्रलोभन तक दिये जाते हैं। लगभग सभी कार्यक्रमों में

शक्ति प्रदर्शन, राजनीतिक संदेश देना, योजनाओं का प्रचार करना या नेता की लोकप्रियता दिखाना होता है। जब इन आयोजनों में अव्यवस्था के कारण हादसे (जैसे भगदड़, सड़क दुर्घटना) होते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही बहुआयामी होती है। सरकारी कार्यक्रमों और रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग करने और लोगों को कथित तौर पर जबरन बुलाने के आरोप समय-समय पर लगते रहे हैं। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भाड़े की भीड़ जुटाने के आरोप लगे, जहाँ एक सड़क हादसे में लोगों के हताहत होने के बाद इस मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाए गए। भीड़ प्रबंधन केवल व्यवस्था बनाए रखने का विषय नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की सुरक्षा, आपातकालीन स्थितियों से निपटने की रणनीतियों से गहनता से संबद्ध है। (शेष पेज 2 पर)

## 'न्योता भोज' से पोषण, सहभागिता और संवेदना का विस्तार

### मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से बदलती तस्वीर

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संचालित 'न्योता भोज' कार्यक्रम आज एक सशक्त सामाजिक अभियान का रूप ले चुका है। यह केवल बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की पहल भर नहीं, बल्कि समाज को बच्चों के पोषण, शिक्षा और समग्र विकास से जोड़ने का अभिनव प्रयास है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शुरू हुई यह पहल राज्य में जनसहभागिता आधारित विकास मॉडल का उदाहरण बनती जा रही है। 'न्योता भोज' कार्यक्रम की मूल भावना सरल लेकिन प्रभावशाली है समाज के लोग अपने विशेष अवसरों को आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ साझा करें। (शेष पेज 2 पर)

## भाजपा के षड़यंत्र के कारण ठहर गया कमलनाथ का औद्योगिक विजन

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश की राजनीति में विकास, दृष्टि और जनहित की बात जब भी होती है, तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम प्रमुखता से सामने आता है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जिस तरह से औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता दी, वह आज भी एक मानक के रूप में देखा जाता है। विशेष रूप से छिंदवाड़ा जैसे क्षेत्र, जो कभी विकास की मुख्यधारा से दूर माना जाता था, उसे उन्होंने अपने विजन और कार्यशैली से एक नई पहचान दिलाने का प्रयास किया। कमलनाथ

कमलनाथ की योजनाओं पर क्यों विराम लगा रही भाजपा सरकार?

का राजनीतिक जीवन केवल सत्ता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने हमेशा विकास को केंद्र में रखकर निर्णय लिए। जब वे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि उनका मुख्य उद्देश्य राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसी सोच के तहत उन्होंने उद्योगों के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया। छिंदवाड़ा, जो उनका गृह क्षेत्र है, वहां उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जो न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे प्रदेश के लिए लाभकारी साबित हो सकते थे। (शेष पेज 3 पर)

## सिंगरौली का पॉवर प्लांट: विकास की आड़ में मजदूरों की जान पर खतरा?

### विकास या विनाश: अदानी पॉवर प्लांट पर मजदूरों की मौतों ने खड़े किए सवाल

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले को देश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। यहां स्थापित बड़े-बड़े ताप विद्युत संयंत्र देश की बिजली जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन विकास की इस चमक के पीछे एक स्याह सच भी लगातार उभर रहा है मजदूरों की सुरक्षा, अधिकार और जीवन की अनदेखी। हाल के घटनाक्रमों ने के पावर प्लांट को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले कुछ समय में सिंगरौली स्थित पावर प्लांट में कई मजदूरों की मौत की घटनाएं सामने

आई हैं। स्थानीय स्तर पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि हर माह औसतन 4 से 5 कर्मचारियों की मौत हो रही है। यदि यह आंकड़े सही हैं, तो यह किसी भी औद्योगिक इकाई के लिए अत्यंत गंभीर और चिंताजनक स्थिति है। मजदूर संगठनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि इन घटनाओं के पीछे सुरक्षा मानकों की अनदेखी, उपकरणों की खराब स्थिति और श्रमिकों पर अत्यधिक कार्य दबाव प्रमुख कारण हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की जा रही? (शेष पेज 3 पर)

# जबरन भीड़ जुटाने के चक्कर में अनाथ हुए बच्चों का जिम्मेदार कौन?

(पेज 1 का शेष)

दुर्भाग्यवश, कई बार आयोजकों और प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किये जाते, जिससे जानमाल की हानि होती है। ऐसे मामलों में जिला प्रशासन और कार्यक्रम के आयोजक अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकते और कानून के तहत उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन दुर्भाग्यवश सत्ता के आगे सब नियम धर्म बेकार हैं। अक्सर देखा जाता है कि आयोजनों में लोगों को कार्यक्रम स्थल तक ले आते हैं कि लेकिन कार्यक्रम के बाद उन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाता है। छिंदवाड़ा की घटना भी इस ओर ध्यान खींच रही है। जिस गाड़ी में यह हादसा हुआ वह ओवरलोड थी। और आपातकालीन स्थिति से निपटने के कोई इंतजाम नहीं थे।

### शासन-प्रशासन का एक चेहरा यह भी है- कार्यक्रम में नहीं आये तो लाड़ली बहना योजना के पैसे बैंक खाते में नहीं आएंगे

सड़क हादसे में अपनी जान गंवाने वाली सिया इनवाती की बेटी शीताली इनवाती का बयान सुनकर मन बेहद दुखी और आक्रोश से भर जाता है। उन्होंने बताया कि उनकी माँ को मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में जबरन ले जाया गया और यह कहा गया कि अगर कार्यक्रम में नहीं गईं तो रोजगार गारंटी और लाड़ली बहना योजना के पैसे खाते में नहीं आएंगे। क्या अब मध्यप्रदेश की माताओं-बहनों को उनके हक के पैसे के लिए डराना और धमकाना ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रह गई है? सरकारी योजनाएँ जनता के टैक्स के पैसे से चलती हैं, किसी पार्टी या नेता की निजी संपत्ति नहीं हैं। गरीब महिलाओं को धमकाकर भीड़ इकट्ठा करना सत्ता का घोर दुरुपयोग है और यह बेहद निंदनीय है। शासन-प्रशासन का एक चेहरा यह भी है। जो सबको विचलित कर सकता है। लोगों को यहां तक धमकाया जा रहा है कि कार्यक्रम में नहीं आयोगें तो लाड़ली बहना योजना के पैसे बैंक खाते में नहीं आएंगे। मतलब साफ है कि भीड़तंत्र के इस स्वरूप में साम-दाम-दंड-भेष सबका उपयोग हो रहा है।

### क्या मुआवजे देने से लौट सकती है परिवार की खुशियां?

सरकार ने 04 लाख मुआवजे की घोषणा कर दी, लेकिन क्या सिर्फ घोषणा कर देने से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? अगर किसी परिवार का कमाने वाला सदस्य चला जाए, तो 04 लाख कितने साल चलेंगे? मुआवजा केवल तात्कालिक राहत दे सकता है लेकिन जीवन भर नहीं। यहां सवाल उठता है कि आखिर वह कौनसी मजबूरी होती है कि लोगों को भीड़ का हिस्सा बनाया जाता है। भले ही वह आना पसंद नहीं करते हों। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का अधिकार सरकार को किसने दिया है।

### बीजेपी का कल्चर बन गया है भीड़ जुटाना

हम पिछले एक दशक से देख रहे हैं कि पूरे देश में बीजेपी ने एक ही कल्चर विकसित किया है कि पार्टी या सरकार के आयोजन में अधिक से अधिक लोगों को एकत्रित किया जाये। वह चाहे स्वयं आये या जबरन लाया जाये। इसलिए हम देखते हैं कि बीजेपी के बड़े किसी भी नेता के आयोजन में हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा किया जाता है। इसमें शासकीय मिशनरी का पूरा दुरूपयोग भी होता है। लोगों को डरा धमकाकर या प्रलोभन देकर एकत्रित किया जाता है। यह कल्चर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर या राज्यीय स्तर पर भी भीड़ का जमावड़ा किया जाता है। प्रशासन की शक्ति की चलते गरीब, बेसहाय जनता मजबूरन भीड़ का हिस्सा बनने को मजबूर होती है।

# 'न्योता भोज' से पोषण, सहभागिता और संवेदना का विस्तार

(पेज 1 का शेष)

जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ या अन्य पारिवारिक खुशियों के अवसर पर नागरिक आंगनबाड़ी केन्द्रों में जाकर बच्चों को पौष्टिक भोजन कराते हैं। इससे जहां बच्चों को अतिरिक्त पोषण मिलता है, वहीं समाज में उनके प्रति अपनत्व और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होती है।

### अब जनआंदोलन का स्वरूप लिया

जनवरी से फरवरी 2026 के बीच राज्य भर में 9,763 'न्योता भोज' आयोजन किए गए, जिनसे 1,83,927 बच्चे लाभान्वित हुए। ये आंकड़े इस योजना की लोकप्रियता और प्रभावशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, कांकेर, धमतरी, महासमुंद और जांजगीर-चांपा जैसे जिलों में व्यापक स्तर पर आयोजन हुए, जो यह संकेत देते हैं कि यह पहल अब जनआंदोलन का स्वरूप ले रही है।

### कुपोषण से लड़ाई में कारगर कदम

छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहां बड़ी संख्या में बच्चे ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, कुपोषण एक गंभीर चुनौती रही है। आंगनबाड़ी केन्द्र पहले से ही पूरक पोषण आहार और प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, लेकिन 'न्योता भोज' ने इसमें एक नया आयाम जोड़ दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों के लिए विविध और पौष्टिक भोजन अत्यंत आवश्यक है, जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। 'न्योता भोज' के माध्यम से बच्चों को सामान्य आहार से अलग, स्वादिष्ट और पोषणयुक्त भोजन प्राप्त होता है, जिससे उनके स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।

### महिलाओं की भूमिका और सशक्तिकरण

इस पूरे अभियान में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं और महिला समूह इस कार्यक्रम की रीढ़ हैं। वे न केवल आयोजन को सफल बनाती हैं, बल्कि समुदाय और बच्चों के बीच सेतु का कार्य भी करती हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना और समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाना है।

### महिलाओं के लिए योजनाओं का व्यापक प्रभाव

राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण अभियान, किशोरी बालिकाओं के लिए विशेष कार्यक्रम और महिला स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देने जैसी पहल शामिल हैं। इन योजनाओं का सीधा लाभ महिलाओं और बच्चों को मिल रहा है। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे वे न केवल अपनी आय बढ़ा रही हैं, बल्कि सामाजिक निर्णयों में भी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। 'न्योता भोज' जैसे कार्यक्रमों में भी इन समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है।

### शिक्षा और संस्कार का संगम

आंगनबाड़ी केन्द्र केवल पोषण का माध्यम नहीं, बल्कि बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा और संस्कार का भी केन्द्र हैं। 'न्योता भोज' कार्यक्रम के दौरान जब समाज के लोग बच्चों के साथ बैठकर भोजन करते हैं, तो यह बच्चों में आत्मविश्वास और सामाजिक व्यवहार को भी विकसित करता है। यह पहल बच्चों को यह एहसास कराती है कि वे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनकी देखभाल केवल सरकार ही नहीं, बल्कि पूरा समाज कर रहा है। इससे आंगनबाड़ी केन्द्रों के प्रति बच्चों और अभिभावकों का विश्वास भी बढ़ा है।

### जनभागीदारी से सशक्त होता विकास मॉडल

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कार्यशैली में जनभागीदारी को विशेष महत्व दिया गया है। 'न्योता भोज' इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां सरकार और समाज मिलकर एक साझा लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रहे हैं। सरकार ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अपने पारिवारिक और सामाजिक अवसरों को आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ साझा करें। इस अपील का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है और अधिक से अधिक लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं।

### भविष्य की संभावनाएं

यदि इसी प्रकार जनसहभागिता बनी रही, तो 'न्योता भोज' कार्यक्रम आने वाले समय में कुपोषण के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन बन सकता है। इसके साथ ही यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में विकास की जो नई धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें 'न्योता भोज' जैसी पहलें न केवल वर्तमान को संवार रही हैं, बल्कि भविष्य की मजबूत नींव भी तैयार कर रही हैं। 'न्योता भोज' कार्यक्रम ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब सरकार की नीतियों में संवेदनशीलता और समाज की सहभागिता जुड़ जाती है, तो परिवर्तन निश्चित होता है। यह पहल पोषण, शिक्षा और सामाजिक समरसता के त्रिवेणी संगम के रूप में उभर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ न केवल विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, बल्कि मानवीय मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी के नए मानक भी स्थापित कर रहा है। यह पहल इस बात का प्रमाण है कि सही सोच और सामूहिक प्रयास से समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक भी विकास की रोशनी पहुंचाई जा सकती है।

# ग्राम पंचायत तुआ घोघरा में गर्मी की दस्तक के साथ ही गहराया पानी का संकट

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. सिवनी। गर्मी की शुरुआत के साथ ही सिवनी जिले के विकासखंड धनौरा के अन्तर्गत आने वाला ग्राम पंचायत तुआ घोघरा में पानी की किल्लत से स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं। हालात यह है कि लोगों को पीने के पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। ऐसे में अभी से यह स्थिति है तो आने वाले दिनों में यह समस्या और भी गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों को कहना है कि पूरे गांव में एक नलकूप है, जहां पानी भरने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। तब जाकर पानी मिल पाता है। हमें किसी भी प्रकार से न स्थानीय विधायक योगेन्द्र सिंह बाबा की मदद मिल रही है और न ही पंचायत के माध्यम से पानी की समस्या को हल कर पा रहे हैं। लोगों को पंचायत के माध्यम से पानी की नियमित आपूर्ति की व्यवस्था नहीं होने के कारण कुओं से पानी भरकर काम चलाना पड़ रहा है। पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर दूर कुओं में पानी भरने के लिए जाना पड़ रहा है। पानी की समस्या के चलते गांवों के सभी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर घर जल योजना के माध्यम से पाइपलाइन बिछाई गई है पर अभी तक पानी आपूर्ति नहीं की जा रही है। पाइपलाइन विस्तार के बाद भी ग्रामीणों को राहत नहीं मिल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पानी की आपूर्ति कब शुरू होगी।

# पुलिस की तैयारी कर रहे दो युवकों ने की साइबर ठगी, महाराष्ट्र से हुए गिरफ्तार

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। साइबर एक्सपर्ट पुलिस अधीक्षक साईं कृष्णा एस. थोटा के निर्देश में साइबर ठगी के मामले में नर्मदापुरम पुलिस निरंतर गंभीरता से कार्य कर रही है और उन्हें सफलता भी मिल रही है। जिसमें एएसपी अभिषेक राजन और एसडीओपी जितेंद्र पाठक के निर्देशन में देहात थाना प्रभारी सौरभ पांडे ने साइबर ठगी के दो आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किया है। बताया जाता है कि पकड़े गए साइबर ठग पुलिस की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने ठगी में एक्सिस बैंक के खाते का उपयोग किया है। जिसमें थाना पुलिस द्वारा 1,04,500/ रुपये की साइबर ठगी करने वाले आरोपियों को दीगर राज्य महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। घटना के अनुसार 18/12/2025 को फरियादी को आरोपीगण द्वारा व्हाट्सअप कॉल करके कहा कि आपका पार्सल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है उसको छुड़ाने के लिए रुपए लगेंगे। मैं क्यू आर कोड भेज रहा हूँ उसमे रुपए डाल दो। तुम्हारा पार्सल तुम्हारे घर डिलेवर हो जाएगा। इस प्रकार आरोपीगण द्वारा योजनाबद्ध तरीके से फरियादी को झांसे में लेकर धोखाधड़ी कर उससे कुल 104500/-रुपये ट्रान्सफर करवा लिए। जिसके संबंध में फरियादी द्वारा थाना उपस्थित होकर वित्तीय धोखाधड़ी संबंधी शिकायत की गई। जिस पर से थाना देहात नर्मदापुरम में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 06/2026 धारा 318 (4) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों ने तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए चरणबद्ध तरीके से धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण से संबंधित भौतिक एवं तकनीकि साक्ष्यों को एकत्रित कर आरोपियों को चिन्हित करते हुए दीगर राज्य छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद) एवं जिला जालना महाराष्ट्र से

# भाजपा के षड़यंत्र के कारण ठहर गया कमलनाथ का औद्योगिक विजन

(पेज 1 का शेष)

### 118 एकड़ जमीन की थी स्वीकृत

छिंदवाड़ा में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कमलनाथ ने कई महत्वपूर्ण पहल कीं। इनमें से एक प्रमुख निर्णय था परासिया क्षेत्र के डोमरी ग्राम में 118 एकड़ जमीन को उद्योग विस्तार के लिए आवंटित करना। यह कदम केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक व्यापक दृष्टिकोण था- स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और निवेशकों को आकर्षित करना। इस प्रकार की योजनाएं किसी भी राज्य के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं।

### योजनाओं को निरंतरता नहीं मिल पा रही

कमलनाथ द्वारा उद्योग विस्तार के लिए स्वीकृत की गई 118 एकड़ जमीन को वर्तमान सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया का संकेत है जिसमें पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को निरंतरता नहीं मिल पा रही है। इससे न केवल निवेशकों का भरोसा प्रभावित होता है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाएं भी कमजोर पड़ती हैं। राजनीति में विचारों का मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन विकास के मुद्दों पर निरंतरता बनाए रखना किसी भी जिम्मेदार सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। कमलनाथ ने जिस सोच के साथ उद्योगों के विस्तार की दिशा में कदम उठाए थे, वह केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण था। ऐसे में उन योजनाओं को रोकना या समाप्त करना कहीं न कहीं विकास की गति को प्रभावित करता है।

### छिंदवाड़ा मॉडल में हुई उल्लेखनीय प्रगति

छिंदवाड़ा के संदर्भ में देखें तो यह क्षेत्र कमलनाथ के नेतृत्व में एक मॉडल के रूप में विकसित हो रहा था। यहां सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली। उन्होंने यह साबित किया कि यदि नेतृत्व में स्पष्ट दृष्टि और इच्छाशक्ति हो, तो किसी भी क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है। डोमरी ग्राम में उद्योग विस्तार के लिए जमीन आवंटित करना भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जो भविष्य में हजारों युवाओं के लिए रोजगार का माध्यम बन सकता था।

### भाजपा का यह फैसला राज्य के सकारात्मक पक्ष में नहीं

आज जब उस निर्णय को वापस लिया गया है, तो यह केवल एक परियोजना का रुकना नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी उम्मीदों का भी प्रभावित होना है। स्थानीय जनता, जो रोजगार और विकास की उम्मीद कर रही थी, वह कहीं न कहीं निराश होती है। इसके साथ ही निवेशकों के बीच भी यह संदेश जाता है कि नीतियों में स्थिरता की कमी है, जो किसी भी राज्य के लिए सकारात्मक संकेत नहीं है। कमलनाथ की राजनीति का मूल आधार हमेशा विकास और जनकल्याण रहा है। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक अनुभव का उपयोग प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए किया। उनकी नीतियों में दूरदर्शिता, भविष्य की जरूरत झलकती है और यही कारण है कि उनके द्वारा लिए गए निर्णय आज भी प्रासंगिक हैं।

### भाजपा के इस कदम का नुकसान जनता को ही हुआ

इसके विपरीत, यदि विकास योजनाओं को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा और उन्हें केवल इसलिए रोका जाएगा क्योंकि वे किसी अन्य दल की सरकार द्वारा शुरू की गई थीं, तो इससे अंततः नुकसान जनता को ही होगा। छोटी मानसिकता वाली राजनीति न केवल स्थानीय विकास को बाधित करती है, बल्कि राज्य की समग्र प्रगति को भी प्रभावित करती है। मध्यप्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए यह आवश्यक है कि विकास की योजनाओं में निरंतरता बनी रहे। चाहे सरकार किसी भी दल की हो, यदि कोई योजना जनहित में है और उससे प्रदेश को लाभ मिल सकता है, तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए।

### घोषणा मात्र नहीं धरातल पर उतारने का किया काम

कमलनाथ की कार्यशैली की विशेषता यह रही कि उन्होंने केवल घोषणाओं तक अपने कार्य को सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने का भी प्रयास किया। उन्होंने उद्योगपतियों से संवाद स्थापित किया, निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में काम किया। यही कारण था कि उनके कार्यकाल के दौरान मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाएं बढ़ने लगी थीं और उद्योगों के प्रति एक सकारात्मक माहौल बन रहा था। हालांकि, यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनकी सरकार केवल 18 महीनों तक ही चल पाई। इसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी और वर्तमान में मोहन यादव मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में यह अपेक्षा की जा रही थी कि पूर्व सरकार द्वारा शुरू की गई विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि प्रदेश की प्रगति में निरंतरता बनी रहे। लेकिन जो स्थिति सामने आई, वह कई सवाल खड़े करती है।

# सिंगरौली का पॉवर प्लांट: विकास की आड़ में मजदूरों की जान पर खतरा?

(पेज 1 का शेष)

### सुरक्षा बनाम मुनाफा

औद्योगिक विकास के साथ श्रमिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन आरोप है कि यहां मुनाफे को प्राथमिकता दी जा रही है। कार्य स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों की कमी, प्रशिक्षण का अभाव और आपातकालीन प्रबंधन की कमजोर व्यवस्था जैसी समस्याएं बार-बार उजागर हो रही हैं। यदि किसी संयंत्र में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो यह केवल संयोग नहीं हो सकता। यह एक प्रणालीगत विफलता की ओर संकेत करता है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि कंपनी अपनी कार्यप्रणाली की गंभीर समीक्षा करे और जवाबदेही तय हो।

### सरकार की भूमिका पर सवाल

इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वह इन घटनाओं पर कठोर कार्रवाई करने के बजाय मौन साधे हुए है। जब किसी क्षेत्र में लगातार श्रमिकों की जान जा रही हो तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह निष्पक्ष जांच कराए, दोषियों पर कार्रवाई करे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। लेकिन यदि प्रशासनिक उदासीनता बनी रहती है, तो यह स्थिति और गंभीर हो सकती है।

### जमीन आवंटन और पारदर्शिता का सवाल

के नेतृत्व वाले समूह को सिंगरौली में हजारों एकड़ जमीन दिए जाने को लेकर भी पहले से ही विवाद रहा है। आरोप है कि यह जमीन बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर दी गई और इसमें पारदर्शिता का अभाव रहा। भूमि अधिग्रहण जैसे संवेदनशील विषय में यदि स्थानीय समुदायों की सहमति और उचित मुआवजा सुनिश्चित नहीं किया जाता, तो असंतोष स्वाभाविक है। यह केवल आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और अधिकारों का प्रश्न भी है।

### स्थानीय समुदाय और विस्थापन

सिंगरौली क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं के चलते बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। कई गांवों के लोग अपनी जमीन और आजीविका से वंचित हुए हैं। ऐसे में यदि उन्हें रोजगार और सुरक्षा भी नहीं मिलती, तो यह दोहरी मार साबित होती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें न तो पर्याप्त मुआवजा मिला और न ही स्थायी रोजगार के अवसर। जो लोग प्लांट में काम कर रहे हैं, वे भी असुरक्षित परिस्थितियों में काम करने को मजबूर हैं।

### श्रम कानूनों का पालन कितना?

भारत में श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कई कानून और नियम बनाए गए हैं। इनमें कार्यस्थल पर सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण, कार्य घंटों की सीमा और स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं। लेकिन यदि इनका पालन केवल कागजों तक सीमित रह जाए, तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जरूरत इस बात की है कि श्रम विभाग नियमित निरीक्षण करे और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे। साथ ही, मजदूरों को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए।

### जवाबदेही तय करने की जरूरत

किसी भी दुर्घटना के बाद केवल मुआवजा देना पर्याप्त नहीं है। असली जरूरत है जवाबदेही तय करने की।

क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था?

क्या कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया था?

क्या उपकरण समय-समय पर जांचे गए थे?

इन सवालों के स्पष्ट जवाब सामने आने चाहिए। यदि कहीं भी लापरवाही पाई जाती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है।

### समाधान की दिशा में कदम

स्थिति को सुधारने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने आवश्यक हैं।

**स्वतंत्र जांच आयोग का गठन**– सभी दुर्घटनाओं की निष्पक्ष जांच हो।

**सुरक्षा ऑडिट**– नियमित अंतराल पर प्लांट का थर्ड पार्टी सुरक्षा ऑडिट कराया जाए।

**श्रमिक प्रशिक्षण**– सभी कर्मचारियों को आधुनिक सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाए।

**स्वास्थ्य सुविधाएं**– कार्यस्थल पर आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था मजबूत की जाए।

**पारदर्शिता**– भूमि आवंटन और रोजगार से जुड़ी प्रक्रियाओं को सार्वजनिक किया जाए।

सिंगरौली का पावर प्लांट केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि हजारों लोगों की आजीविका और जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। विकास तभी सार्थक है, जब वह सुरक्षित और समावेशी हो। यदि मजदूरों की जान की कीमत पर उद्योग चलेंगे, तो यह विकास नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक संकट होगा। अब समय आ गया है कि और सरकार दोनों मिलकर इस स्थिति को गंभीरता से लें और ठोस सुधारात्मक कदम उठाएं। मजदूर केवल उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि इस विकास यात्रा के वास्तविक आधार हैं। उनकी सुरक्षा, सम्मान और अधिकार सुनिश्चित करना ही सच्चे अर्थों में प्रगति का पैमाना होना चाहिए।

# रामनवमी के पावन अवसर पर ब्रह्माकुमारीज़ द्वारा नौ देवियों की चैतन्य झांकी का भव्य आयोजन

-प्रमोद बरसले

*जगत प्रवाह. टिमरनी।*

रामनवमी के पावन अवसर पर प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा टिमरनी के मंडी प्रांगण में नौ देवियों की चैतन्य झांकी का भव्य एवं आकर्षणमय आयोजन किया गया एवं 108 दीपकों के द्वारा महा आरती की गई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विभिन्न स्थानों से आए संतों एवं नगर के विशिष्ट राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हुआ। इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं एवं नगरवासियों ने उपस्थित होकर झांकी के दर्शन किए और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव किया। झांकी के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि प्रत्येक नारी में देवी स्वरूप के दिव्य गुण निहित होते हैं। परमात्मा राम द्वारा सिखाए जा रहे राजयोग के अभ्यास से नारी यदि अपने भीतर के दिव्य गुणों को पहचानकर उन्हें जीवन में धारण करे, तो वह परिवार और समाज दोनों को नई दिशा दे सकती है और जीवन को श्रेष्ठ, सुखमय और संतुलित बनाया जा सकता है। इस अवसर पर ब्रह्माकुमारी भव्यता बहन ने अपने संबोधन में कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है क्योंकि अपने जीवन में इतने भी विघ्न आने के बाद भी उन्होंने अपनी धैर्यता,गंभीरता, सरलता, स्थिरता व मानसिक संतुलन और अन्य दिव्य संस्कारों के आधार पर उन पर विजय प्राप्त की। अंत में सभी को रामनवमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं दी।

## सम्पादकीय

# डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर चेताया

वैश्विक राजनीति के परिदृश्य में एक बार फिर तनाव की लहर देखने को मिल रही है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। यह चेतावनी केवल दो देशों के बीच टकराव का संकेत नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया में बदलते शक्ति समीकरणों और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की जटिलताओं को भी उजागर करती है। अमेरिका और ईरान के बीच संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और सैन्य गतिविधियों को लेकर दोनों देशों के बीच कई बार टकराव की स्थिति बनी है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में पहले से ही अस्थिरता का माहौल है और छोटे-छोटे घटनाक्रम भी बड़े संघर्ष का रूप ले सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी का मुख्य केंद्र ईरान की कथित आक्रामक गतिविधियां और उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंताएं हैं। अमेरिका लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि ईरान इन आरोपों को खारिज करता रहा है। ट्रंप प्रशासन के दौरान पहले भी ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका के बाहर निकलने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था।

इस ताजा चेतावनी के पीछे केवल सुरक्षा चिंताएं ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक हित भी जुड़े हुए हैं। अमेरिका अपने सहयोगी देशों विशेषकर इजराइल और खाड़ी देशों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है। वहीं, ईरान अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखने और मजबूत करने की कोशिश में लगा है, जिससे टकराव की स्थिति और जटिल हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की चेतावनियां केवल कूटनीतिक दबाव बनाने का माध्यम भी हो सकती हैं। अमेरिका अक्सर आर्थिक प्रतिबंधों और राजनीतिक बयानबाजी के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाता रहा है। दूसरी ओर, ईरान भी अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कड़ा रुख अपनाता है।

इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ता है। तेल आपूर्ति, व्यापार मार्गों और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है। यदि यह तनाव बढ़ता है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, खासकर उन देशों पर जो ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत के ईरान के साथ पारंपरिक व्यापारिक और ऊर्जा संबंध रहे हैं, वहीं अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत हो रही है। ऐसे में भारत को संतुलित कूटनीति अपनानी पड़ती है, ताकि उसके राष्ट्रीय हित सुरक्षित रह सकें। अंततः डोनाल्ड ट्रंप की यह चेतावनी केवल एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के बदलते स्वरूप का संकेत है। यह आवश्यक है कि दोनों देश संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान खोजें, ताकि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति बनी रहे। बढ़ते तनाव के इस दौर में संयम, संवाद और समझदारी ही स्थायी समाधान

## सियासी गहमागहमी

### मोहन कैबिनेट में विस्तार की सुगबुगाहट

मध्यप्रदेश में मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। यह सुगबुगाहट केवल पदों के बंटवारे तक सीमित नहीं, बल्कि इसके पीछे संगठनात्मक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और आगामी राजनीतिक रणनीति जैसे कई पहलू जुड़े हुए हैं। कैबिनेट विस्तार को अक्सर सरकार के प्रदर्शन, जन अपेक्षाओं और राजनीतिक समीकरणों को साधने के अवसर के रूप में देखा जाता है। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि नए चेहरों को मौका देकर सरकार ताजगी का संदेश दे सकती है, वहीं अनुभवी नेताओं को शामिल कर प्रशासनिक मजबूती भी सुनिश्चित की जा सकती है। इसके साथ ही सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधना भी एक अहम चुनौती होगी। विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देकर सरकार व्यापक जनाधार को मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना भी इस विस्तार का एक प्रमुख उद्देश्य माना जा रहा है।

### CM विष्णुदेव साय के कार्यों को PM मोदी ने सराहा

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सराहना किया जाना राज्य की प्रशासनिक दिशा और नीतिगत प्राथमिकताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। यह केवल एक औपचारिक प्रशंसा नहीं, बल्कि सरकार के कामकाज पर केंद्र की संतुष्टि और विश्वास का प्रतीक भी है। विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सुशासन, जनकल्याण और विकास के मुद्दों पर तेजी से काम करने की कोशिश की है। खासकर आदिवासी क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और पारदर्शिता पर जोर देना उनकी कार्यशैली की पहचान बनता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री की सराहना से न केवल राज्य सरकार का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि प्रशासनिक तंत्र को भी और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलेगी। राजनीतिक दृष्टि से भी यह सराहना अहम है, क्योंकि इससे यह संदेश जाता है कि राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित है। आने वाले समय में यह तालमेल विकास परियोजनाओं की गति को और तेज कर सकता है। कुल मिलाकर, यह प्रशंसा राज्य की नीतियों को सही दिशा में बढ़ने का संकेत देती है।

## हफ्ते का कार्टून

## ट्वीट-ट्वीट

ऊना की दीक्षा आज भी इंसाफ के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बीते 10 सालों से पीड़ित न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं। अपमान, हिंसा और हत्या - BJP शासित गुजरात में दलितों, आदिवासियों की यही हकीकत बना दी गई है।

मोदी जी के इसी असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण मॉडल को पूरे देश पर थोपा जा रहा है।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक बार फिर प्रदेश को कर्ज के दलदल में धकेल दिया है।

नीति आयोग भी अपनी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के बढ़ते कर्ज पर चिंता व्यक्त कर चुका है लेकिन राज्य सरकार को इस बारे में कोई चिंता नहीं है।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

## राजवीरों की बात

# डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार : राष्ट्र चेतना के प्रखर प्रेरणास्रोत

समता पाठक/जगत प्रवाह

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रवादी चिंतन की धारा में केशव बलिराम हेडगेवार का नाम अत्यंत सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। वे न केवल एक प्रखर स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि संगठन निर्माण की अद्भुत क्षमता से युक्त दूरदर्शी व्यक्तित्व भी थे। उनके जीवन का मूल उद्देश्य राष्ट्र को सशक्त, संगठित और आत्मनिर्भर बनाना था। डॉ. हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को महाराष्ट्र के नागपुर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित बलिराम पंत हेडगेवार संस्कृत के विद्वान थे। बचपन से ही केशव में राष्ट्रभक्ति की भावना प्रबल थी। अंग्रेजी शासन के प्रति उनके मन में विरोध की भावना प्रारंभ से ही दिखाई देने लगी थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नागपुर में प्राप्त की, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए वे कोलकाता गए, जहां उन्होंने चिकित्सा (मेडिकल) की पढ़ाई की। इसी दौरान वे क्रांतिकारी गतिविधियों और राष्ट्रवादी विचारधारा से गहराई से प्रभावित हुए।

कोलकाता प्रवास के दौरान उनका संपर्क अनेक क्रांतिकारियों से हुआ, जिससे उनके मन में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी की प्रेरणा और भी मजबूत हुई। नागपुर लौटने के बाद उन्होंने चिकित्सा सेवा के साथ-साथ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी सक्रिय सदस्य रहे और असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उनके जोशीले भाषणों और राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। डॉ. हेडगेवार का मानना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से राष्ट्र का पूर्ण उत्थान संभव नहीं है, बल्कि समाज को भीतर से संगठित और सशक्त बनाना भी आवश्यक है। इसी विचार के साथ उन्होंने वर्ष 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना का उद्देश्य समाज में अनुशासन, संगठन और राष्ट्रभक्ति की भावना को विकसित करना था। उन्होंने स्वयंसेवकों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का प्रयास किया।

डॉ. हेडगेवार का जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण और अनुशासित था। वे व्यक्तिगत प्रसिद्धि से दूर रहकर कार्य करने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो और राष्ट्रहित को सर्वोपरि माने। उन्होंने अपने जीवनकाल में संगठन के विस्तार के लिए अथक परिश्रम किया और हजारों युवाओं को राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित किया। उनकी नेतृत्व क्षमता और संगठन कौशल के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तेजी से फैलने लगा। उन्होंने शाखा पद्धति के माध्यम से युवाओं में शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया। उनका यह प्रयास भारतीय समाज को एक सशक्त और संगठित रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुआ। 21 जून 1940 को डॉ. हेडगेवार का निधन हो गया, लेकिन उनके द्वारा स्थापित संगठन और उनके विचार आज भी जीवंत हैं। उन्होंने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि राष्ट्र निर्माण केवल शब्दों से नहीं, बल्कि निरंतर कर्म, अनुशासन और समर्पण से होता है। डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार का जीवन प्रेरणा, त्याग और राष्ट्रभक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। उनका योगदान भारतीय समाज और राष्ट्र के निर्माण में सदैव स्मरणीय रहेगा।

# प्रदेश के संतुलित एवं समावेशी विकास के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित: पुष्कर सिंह धामी

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक कर राज्य के विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन व्यवस्था को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से अपेक्षा की कि वे जनपदों का नियमित भ्रमण कर संचालित विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर वास्तविक प्रगति का आकलन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता योजनाओं का धरातल पर प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनपद स्तर पर विकास कार्यों की निरंतर निगरानी से न केवल योजनाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि जनता का विश्वास भी मजबूत होगा। उन्होंने मंत्रीगणों से कहा कि वे स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से संवाद स्थापित कर योजनाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी लें। जन-मन की समस्याओं के त्वरित समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागीय मंत्री अपने विभागों की नियमित और गहन समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी विशेष बल दिया। सड़क, पेयजल, ऊर्जा, सिंचाई और भवन निर्माण जैसे विभाग यदि समन्वित रूप से कार्य करें तो विकास परियोजनाएं तय समय-सीमा में पूर्ण की जा सकती हैं और जनता को शीघ्र लाभ मिल सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जन अपेक्षाओं के अनुरूप विकास को नई गति देने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का समग्र और संतुलित विकास ही सरकार का मूल लक्ष्य है, और इसके लिए नीति निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है।

# भोजन के अधिकार अंतर्गत बुकिंग के आधार पर अनिवार्य रूप से घर-घर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना प्रशासनिक जवाबदेही: अजय खरे

-अर्चना शर्मा

जगत प्रवाह. टीबा। समता सम्पर्क अभियान के राष्ट्रीय संयोजक लोकतंत्र सेनानी अजय खरे ने कहा कि बुकिंग के आधार ईंधन गैस सिलेंडरों की घर घर आपूर्ति व्यवस्था ठप किए जाने के सवाल पर जिला प्रशासन यदि ईंधन गैस सिलेंडर प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता तो गैस सिलेंडर गोदामों में अनावश्यक भीड़ की समस्या से शीघ्र ही छुटकारा मिल जाता। खरे ने कहा कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के लिए मारा-मारी की अप्रिय स्थिति निर्मित होना अच्छी बात नहीं है। अजय खरे ने कहा कि अभी भी आम आदमी को गैस सिलेंडर लेने के लिए काफी भाग दौड़ करनी पड़ रही है। इधर देखने को यह मिला कि गैस सिलेंडर की घर-घर आपूर्ति करने की जगह प्रशासन के द्वारा सिलेंडर गोदामों पर भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस भेजकर लाइन लगवाना शुरू करवा दिया। इस बात से जनसाधारण में यह संदेश गया कि लोगों को गोदाम में ही सिलेंडर मिलेगा और फिर बड़ी संख्या में भरा गैस सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं की बढ़ोतरी हुई और लोगों की परेशानी बढ़ी। खरे ने कहा कि गोदाम से सिलेंडर लेने के बावजूद आम उपभोक्ताओं से अनावश्यक रूप से होम डिलीवरी चार्ज बसूला जाना सरासर गलत है। अव्यवस्था का गलत लाभ कालाबाजारी करने वालों ने उठाया। लोगों ने मजबूरी में अधिक दाम देने के बाद भी भरा गैस सिलेंडर मिल जाने पर राहत महसूस की। खरे ने कहा कि यह भारी विडंबना है कि एक तरफ लोगों को खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर लेने के लिए समय सीमा निर्धारित है और आने वाले समय में गैस सिलेंडर में 14.2 किलो ईंधन गैस को 4.2 किलो कम करके 10 किलो उपलब्ध करने का प्रस्ताव है वहीं पेट्रोल डीजल को लेकर इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। श्री खरे ने कहा कि ईंधन गैस आपूर्ति भोजन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। प्रशासन की जवाबदेही है कि आम उपभोक्ताओं के घरों में बुकिंग के आधार पर गैस सिलेंडर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और पीएनजी के लिए अनावश्यक दबाव नहीं बनाया जाए।

# बैरसिया में चैतन्य दैवी झांकी का भव्य आयोजन, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

- संवाददाता

जगत प्रवाह. भोपाल। बैरसिया क्षेत्र स्थित दुर्गा चौक मंदिर (बसाई रोड) पर आयोजित नौ दिवसीय चैतन्य दैवी झांकी इन दिनों श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और मां दुर्गा, मां सरस्वती एवं मां लक्ष्मी की सजीव एवं मनमोहक झांकियों के दिव्य दर्शन कर भाव-विभोर हो उठे। यह भव्य आयोजन प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में किया गया है, जिसमें आध्यात्मिकता और सामाजिक जागरूकता का सुंदर समन्वय देखने को मिली। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित आयुष शर्मा द्वारा विधिवत पूजा-अर्चना के साथ हुई, जिसके बाद झांकियों का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉ. राजयोगी बीके आशीष भाई के मार्गदर्शन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नन्हे-मुन्ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत नशामुक्ति पर आधारित नाटक ने सभी का ध्यान आकर्षित किया और समाज को एक सशक्त संदेश दिया कि नशा न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है।

# रायपुर में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के अंतर्गत पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय खेल मैदान रायपुर में आयोजित पुरुष 88 किलोग्राम भारोत्तोलन प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया। प्रतियोगिता में देशभर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने भाग लिया और कड़े मुकाबले देखने को मिले। इस प्रतिस्पर्धा में अरुणाचल प्रदेश के रुबा ताडु ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 274 किलोग्राम वजन उठाकर पहला स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने स्नैच में 117 किग्रा तथा क्लीन एंड जर्क में 157 किग्रा वजन उठाकर शीर्ष स्थान सुनिश्चित किया। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश के देवरकोंडा प्रेम सागर रहे, जिन्होंने कुल 270 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता। वहीं अरुणाचल प्रदेश के ही सोरम हिटलर टाग्रू ने 262 किलोग्राम के साथ तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में ओडिशा के सनातन मलिक (249 किग्रा) चौथे स्थान पर रहे, जबकि असम के प्रीतम सोनोवाल (248 किग्रा) ने पांचवां स्थान प्राप्त किया। मध्यप्रदेश के पृथ्वीराज चौहान (226 किग्रा) छठे स्थान पर रहे। इसके अलावा त्रिपुरा के डेनियल जमातिया (192 किग्रा), गोवा के एलेस्टर गोम्स (152 किग्रा), तेलंगाना के सिद्दाबोइना नवीन (146 किग्रा) और छत्तीसगढ़ के छत्रपाल ठाकुर (130 किग्रा) ने भी प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने-अपने प्रदर्शन से अनुभव हासिल किया। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के इस आयोजन से यह स्पष्ट होता है कि आदिवासी क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। सही मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर ये खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं।

### डॉ. राममनोहर लोहिया के जन्मदिवस पर विशेष

# डॉ. लोहिया की प्रासंगिकता

रघु ठाकुर
सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक और समाजवादी नेता

23 मार्च समाजवादी नेता डॉ. राममनोहर लोहिया का जन्म दिन है। उनकी युवा अवस्था जर्मनी से शिक्षा पूरी करके और देश आने के बाद आजादी के आंदोलन में बीती। लाहौर से लेकर आगरा जेल तक भीषण यातना के साथ उन्होंने जेल यात्रा पूरी की। 1945 में जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन शुरू किया, जिसकी शुरुआत गोवा में नागरिक अधिकारों के साथ शुरू हुई और वह बाद में गोवा मुक्ति आंदोलन में बदल गया। इस आंदोलन में वे आग्वा किले में बनाई गई जेल में रहे जो बहुत कष्टकारी जेल यात्रा थी। आजादी के बाद भी वे बहुत बार देश की आजाद सरकार की जेलों में रहे परंतु उनकी कानपुर की जेल यात्रा भी काफी तकलीफप्रद थी। जिस प्रकार ब्रिटिश हुकुमत या पुर्तगाली हुकुमत ने उन्हें शत्रु मानकर व्यवहार किया था कुछ उससे भी अधिक बुरा व्यवहार देश की आजाद सरकार ने उनके साथ कानपुर जेल में किया था। लोहिया के जीवन के बहुत पहलु हैं, भाषा, राजनीति, धर्म, सिविल नाफरमानी, कृषि नीति, आदि कितने ही ऐसे विषय हैं जिन्हें लोहिया ने अपने विचारों से पुष्ट कर देश के समक्ष रखा। उन विषयों पर अब भी लोहिया के विचारों के आगे कम से कम मूल और सूत्र रूप में कोई उसके आगे चिन्तन नहीं हो सका है। हालांकि समयकाल के साथ चिन्तन की धारा को निरंतर आगे ले जाने के प्रयास होना चाहिए।



कुछ मित्र मुझसे पूछते हैं कि आप सदैव दुनिया की चर्चा करते हैं, तो उसमें लोहिया ही क्यों जरूरी है। इस 21वीं सदी में, बाजारवाद के युग में, वैश्वीकरण के दौर में, लोहिया के विचारों की क्या प्रासंगिकता है? मैं उनको कहता हूँ कि, लोहिया की श्सप्तक्रांत्यि आज भी अपने मूल और सूत्र रूप में समता के विश्व का आधार है। मैं इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दों पर आज डॉ. लोहिया को वर्तमान काल की प्रासंगिकता को कसौटी पर कसूँगा।

हिन्दुस्तान की संसद को डॉ. लोहिया ने एक नया दर्शन व सूत्र दिया था। देश की संसद केवल खाता बही रखने व पेश करने वाली मुनीम साहब की खाता वही नहीं है। बल्कि देश के गरीब और आम आदमी का प्रतिबिम्ब है। लोहिया ने हिन्दुस्तान की संसद में श्तीन आने बनाम पन्द्रह आने वाला्य भाषण देकर गरीबों की संसद बना दिया, और उस अल्प काल याने लगभग 5-6 वर्षों के दौरान देश का गरीब चाय वाला, पान वाला, छोटा व्यापारी, गाँव का किसान जो आज संसद की कार्यवाही को देखना तो दूर सुनना भी नहीं चाहता, लोहिया के संसदीय जीवन के दौरान संसद की कार्यवाही को रेडियो पर सुनते थे। लोहिया संसद में बोलते थे, गरीबों की बात उठाते थे और हजारों मील दूर बैठा किसान-मजदूर लोहिया के भाषण में अपने जीवन की व्यथा व कथा देखता था। इसीलिये डॉ लोहिया ने कहा था कि मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, सिवाय इसके कि देश का गरीब आदमी मुझे अपना आदमी मानते हैं। पिछले 1967 के बाद से संसद की चाल और चरित्र बदल चुका है। अब संसद में गरीबों की भागीदारी नहीं है बल्कि संसद अमीरों की बन गई। तीन-चौथाई से अधिक सांसद आज करोड़पति हैं जबकि देश के 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिये मोहताज और अपना वोट बेचने को लाचार हैं। क्या संसद का यह बदला हुआ स्वरूप गरीबों की संसद से अमीरों की संसद, भारतीय संसद से वैश्वकीकृत संसद में परिवर्तिन, संप्रभु संसद से विश्व व्यापार के समझौते की गुलाम संसद तक में परिवर्तन क्या आज भी लोहिया को प्रासंगिक सिद्ध नहीं करता? आज संसद देश में आमजन के लिये विश्वसनीय नहीं है, यह लोकतंत्र के लिये एक बुरा दौर है। संसद की कार्यवाही को आम आदमी देखना ही नहीं चाहता। किसी नग्नावतार अभिनेता-अभिनेत्री की फिल्म को देखने के लिये, क्रिकेट के मैच को देखने के लिये देश का मध्य व उच्च वर्ग बैचेन रहता है परंतु संसद की कार्यवाही को देखना तो दूर, शुरू होने के पूर्व टी.वी. बंदकर देता है। आज की संसद संवाद करने की जगह बहिष्कार की संसद बन गई। कई बार तो यह लगता है कि सत्ता पक्ष व प्रतिपक्ष बहिष्कार चाहते हैं। ताकि सत्ता पक्ष अपने मनोनुकूल निर्णय करने को स्वतंत्र रहे और विपक्ष नकली क्रांतिकारी नकाब ओढ़े हुए बने रहे।

लोहिया ने 1950 के दशक में 18 साल के बालिग मतदाता द्वारा समूची दुनिया की एक निर्वाचित विश्व संसद के गठन की कल्पना प्रस्तुत की थी। आज अगर यह विश्व संसद बनी होती तो क्या रूस व यूक्रेन युद्ध आरंभ हो पाता? अफगानिस्तान-पाकिस्तान, ईरान-इजरायल, इजरायल-फिलिस्तीनी जैसे जो सीमाई आजादी या खनिज संपदा को लेकर क्या सांपत्तिक युद्ध हो पाते? क्या आतंकवाद की घटनायें होती? क्या वैश्विक पूँजीवाद अपने आगोश में विश्व को लेने में समर्थ होता? अभी दुनिया जो तीसरे युद्ध की ओर बढ़ रही है, इसका अंत क्या होगा, कैसे होगा, कितना विनाशकारी होगा? इन सवालों की कल्पना कठिन है। कहने को यूएनओ है पर वह एक लकवाग्रस्त संस्था है। इजरायल,अमेरिका बनाम ईरान युद्ध शुरू होने के बाद यूएनओ के महासचिव ने एक पुकार लगाई है कि श्युद्ध समाप्त होना चाहियेय, परंतु कर्म के स्तरपर कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि वे युद्धरत महाशक्तियों के बारे में एक निंदा का शब्द भी नहीं बोल पाते। यूएनओ की महासभा की सुरक्षा परिषद की बैठक भी नहीं बुला पाते। क्या ऐसा यूएनओ दुनिया की समस्याओं का हल कर सकता है? दूसरी ओर आप कल्पना करें कि अगर लोहिया की कल्पना के अनुसार निर्वाचित विश्व संसद बनी होती तो क्या दुनिया इस विश्व युद्ध के संकट व त्रासदी को झेलने को विवश होती? क्या जिस दुनिया का निर्माण आज हो रहा है उसमें एक व्यक्ति वारेन वफेट के पास 70 लाख करोड़ की नगदी है और दूसरा व्यक्ति 70 रुपये पर जिंदा है ऐसी विषम दुनिया बन पाती। क्या दुनिया में नशे का व्यापार हो पाता? क्या दुनिया में व्यक्ति व राज्य की तानाशाही हो पाती? अगर विश्व संसद बनी होती या बन जाए तो न केवल इन सब समस्याओं से निजात मिलेगी बल्कि एक सुंदर दुनिया बन जाये। क्या यह लोहिया की प्रासंगिकता महसूस नहीं कराती?

राजनैतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र लगभग समाप्त है। दल व्यक्तिपरक और परिवारपरक बन गये हैं। एक नये प्रकार के लोकतांत्रिक आवरण में ढके क्रूर पारिवारिक सामंतवाद का न केवल उदय हो रहा है बल्कि यह व्यापक रूप से फैल चुका है। लोहिया ने लगातार सत्ता के विकेंद्रीकरण चौखंभा राज्य, दलों में आंतरिक लोकतंत्र की बात को मजबूती से उठाया था और व्यक्तिपरक दलों को लोकतंत्र की तरफ झुकने के लिये लाचार किया था। आज राजनीतिक दलों की गिरावट, अलोकतांत्रिक कार्यप्रणाली जातिवाद और परिवारवाद, दलीय तानाशाही, क्या लोहिया की प्रासंगिकता सिद्ध नहीं करती है?

डॉ. लोहिया ने महात्मा गांधी के दुनिया को दिये सबसे बड़े हथियार सत्याग्रह को अपने काल के अनुकूल एक नये स्वरूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने सिविल नाफरमानी को लोकतंत्र की बुनियाद के साथ जोड़ा, सिविल नाफरमानी को संसद को बेहतर बनाने के लिये, उसके साथ रिश्ता जोड़ा। यह लोहिया ही कहते थे कि श्अगर सड़कें सूनी रहेगी तो संसद आवारा हो जायेगी। संसद तभी कोई अच्छा कानून पारित कर सकती है जब जनता का दबाव बने। अहिंसक सिविल नाफरमानी के बजाय संसद बांझ है। जो कोई नई रचना नहीं कर सकती है। लोहिया ने अहिंसक सिविल नाफरमानी को नागरिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष माना और नागरिक अधिकारों का सबसे मजबूत हथियार भी बनाया। वे कहते थे कि वे ऐसा व्यक्ति गढ़ना चाहते हैं जो स्वभाव से सत्याग्रही हो, याने व्यक्ति अपने आपमें ही हर अन्याय की मुखालपत वाला बने और जहां कहीं भी कोई अन्याय हो वहाँ उसका प्रतिकार करे। क्या आज की परिस्थितियां जो दलीय और राजकीय तानाशाही की गिरफ्त में है। क्या लोहिसा की प्रासंगिकता सिद्ध नहीं करती?

डॉ. लोहिया ने महात्मा गांधी को इस अर्थ में भी पुर्नजीवित किया, कि आजादी के बाद एक विचार देश के समक्ष कुछ समूहों के द्वारा रखा था कि आजादी के बाद देश में सत्याग्रह की क्या आवश्यकता है? अपनी सरकार है, अब सत्याग्रह की जरूरत नहीं है। पर डॉ. लोहिया ने कहा कि सत्याग्रह एक सर्वकालिक गांधी का दिया हुआ औजार है और सतत सत्याग्रह ही एक बेहतर देश, समाज संसद और राजनीति का निर्माण कर सकता है। आज जिस प्रकार लोग भयभीत हैं, अपनी बात हिम्मत से कहने में डरते हैं, क्या उन्हें निर्भय बनाने के लिये लोहिया की अहिंसक सिविल नाफरमानी सबसे सशक्त माध्यम नहीं है? आज राज्य निरंकुश बन रहा है और राजनैतिक नेतृत्व दब्बू व बौना हो रहा है। तब क्या इस हालत को बदलने के लिये लोहिया की अहिंसक सिविल नाफरमानी सबसे उपयुक्त माध्यम नहीं है? एक जीवित मुर्दा व्यक्ति को जीवित जीवंत व्यक्ति में बदलने के लिये, सड़कों को गरमा कर, संसद को उपयोगी बनाने के लिये, देश को गरमाकर, केन्द्रीकरण और तानाशाही की ओर बढ़ती सरकार के कदमों के सामने अंगार बिछाने के लिये, अहिंसक नाफरमानी के अलावा कया और केई विकल्प हो सकता है? और क्या यह लोहिया की प्रासंगिकता नहीं है?

# एकजुट होकर प्लास्टिक प्रदूषण को हराएँ

**पर्यावरण की फिक्र**

**डॉ. प्रशांत सिन्हा**
पर्यावरणविद

प्लास्टिक प्रदूषण आज पूरी मानवता के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। हर रोज हजारों टन प्लास्टिक कचरा नदियों, समुद्रों और जमीन पर फैल रहा है, जिससे जल, वायु और मृदा सभी प्रकार से प्रदूषित हो रही हैं। विश्व भर में प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या ने विगत वर्षों में एक गंभीर आयाम ले लिया है। पर्यावरण के लिए यह एक चुनौती बन चुकी है, जिसका सामना हम सभी को मिलकर करना होगा। इस समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक, नीति निर्माता, उद्योग जगत और आम जनता सभी को एक साथ आगे आना होगा। प्लास्टिक का उपयोग दैनिक जीवन में इतना बढ़ गया है कि इसके बिना जीवन की कल्पना कर पाना मुश्किल है। लेकिन इसके निपटान में अक्षमता ने पर्यावरणीय संकट को जन्म दिया है। प्लास्टिक कचरे का बड़ा हिस्सा नदियों, समुद्रों में जमा हो रहा है, जिससे जलीय जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। आज दुनिया के सामने सबसे गंभीर पर्यावरणीय मुद्दों में से एक है। चूंकि हमारे द्वारा उपयोग किया जाने वाला अधिकांश प्लास्टिक टूटता नहीं है और आसानी से घुल जाता है, यह धीरे-धीरे हमारे महासागरों में भर रहा है, जिसे विघटित होने में सदियाँ लगेंगी, जिससे जलीय जीवन, मानव स्वास्थ्य और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जबरदस्त समस्याएँ पैदा होंगी। अध्ययनों का अनुमान है कि 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा।

इस समस्या का समाधान करने के लिए कई पहल की जा रही हैं। पहला कदम तो यही है कि प्लास्टिक के उपयोग को कम करना। इसके लिए बाजार में बायोडिग्रेडेबल और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक के विकल्प उपलब्ध कराने होंगे। इसके साथ ही, रीसाइक्लिंग को और अधिक प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। दूसरा, उपभोक्ताओं को जागरूक करना जरूरी है कि वे अपने दैनिक उपयोग में प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें और जहां संभव हो सके, पुनः उपयोग या रीसाइक्ल करें। इसके लिए शिक्षा और जागरूकता अभियानों का आयोजन महत्वपूर्ण है। तीसरा, सरकारों को प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सख्त नीतियाँ और विनियमन लागू करने चाहिए। इसमें प्लास्टिक के उत्पादन, वितरण, उपयोग और निपटान को लेकर सख्त दिशा-निर्देश शामिल होने चाहिए। चौथा, नवाचार और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करना होगा ताकि प्लास्टिक कचरे को पुनः उपयोगी संसाधनों में परिवर्तित किया जा सके। बायोप्लास्टिक्स, प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने की प्रक्रियाएं और अन्य नवाचारों को विकसित और लागू करने की जरूरत है।

दुनिया के कई वैज्ञानिक प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक समाधान जो सामने आया है वह है प्लास्टिक खाने वाला एंजाइम। जापान में 2016 में, एक वैज्ञानिक ने एक प्लास्टिक खाने वाले एंजाइम की खोज की जो पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) को तोड़ने में सक्षम था- प्लास्टिक का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला है। यह एंजाइम, जिसे इडियोनेला सकाएन्सिस 201-एफ 6 के नाम से जाना जाता है, एक बैक्टीरिया है जो पेटेज नामक एंजाइम को स्रावित करके प्लास्टिक को पचा सकता है और खाद्य स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए पीईटी में कार्बन को ग्रहण कर सकता है। हालाँकि टूटने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी बनी हुई है, वैज्ञानिक इसे तेज करने के लिए काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम एंजाइम की आणविक संरचना को संशोधित करने में सक्षम हो गई है, और इसे मूल रूप से पीईटी की तुलना में 20% तेजी से उपभोग करने के लिए संशोधित किया है। वैज्ञानिकों ने एक चुंबकीय कुंडल बनाया है जो समुद्र में माइक्रोप्लास्टिक को लक्षित करने में सक्षम है। यह प्रायोगिक नैनोटेक्नोलॉजी समुद्री जीवन को कोई नुकसान पहुंचाए बिना पानी में माइक्रोप्लास्टिक को तोड़ने में सक्षम है। मानव बाल से भी पतले, ये कुंडलियाँ माइक्रोस्कोप के नीचे बेड स्प्रिंग्स की तरह दिखती हैं, और नाइट्रोजन और मैंगनीज नामक एक चुंबकीय धातु में लेपित होती हैं। जब वे ऑक्सीजन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तो वे प्लास्टिक पर हमला करते हैं और इसे तोड़ने में मदद कर सकते हैं। इस अध्ययन के सह-लेखक जियाओगुआंग डुआन ने पाया कि शुरुआती प्रयोगों में आठ घंटे की अवधि में नैनो-कॉइल्स में माइक्रोप्लास्टिक्स में 30% से 50% की कमी दर थी।

हम सभी को यह समझना होगा कि प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या केवल सरकारों या नीति निर्माताओं की नहीं है; यह हम सभी की समस्या है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक व्यवसाय इस समस्या के समाधान में योगदान दे सकता है। यह समय है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें और एक स्वच्छ, हरित और स्थायी भविष्य के लिए कदम उठाएं।

# उड़ान भरो- आसमान तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है

## बदलते भारत में विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सफलता के सूत्र

**आज की बात**

**प्रवीण कक्कड़**
स्वतंत्र लेखक

इसी समय देश के लाखों विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं के बाद अपने भविष्य की दहलीज पर खड़े हैं। यह क्षण केवल परिणामों के इंतजार का नहीं, बल्कि गहन आत्म-मंथन का है। हर युवा को स्वयं से पूछना चाहिए- मेरी वास्तविक रुचि क्या है? जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाएँ कक्षा के बाहर होती हैं, जहाँ परिणाम अंकपत्र नहीं, बल्कि आपका व्यक्तित्व तय करता है।

### रूढ़ियों को तोड़कर रुचियों को पहचानें

10वीं और 12वीं की परीक्षाएँ जीवन के अहम पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। अक्सर विद्यार्थी सामाजिक दबाव या मित्रों की देखा-देखी विषय चुन लेते हैं, जो बाद में बोझ बन जाता है। 2026 का भारत अब सीमित विकल्पों का देश नहीं रहा। आज विज्ञान, वाणिज्य और कला- तीनों ही धाराएँ समान अवसरों के द्वार खोलती हैं। यदि किसी को मनोविज्ञान या भूगोल में रुचि है, तो वह उसमें विशेषज्ञ बन सकता है। वहीं, तकनीक प्रेमियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे आधुनिक क्षेत्र इंतजार कर रहे हैं। याद रखें, गलत चुनाव केवल एक साल नहीं, बल्कि पूरे भविष्य को प्रभावित करता है।

### डिग्री के साथ स्किल भी ज़रूरी

12वीं के बाद का समय विशेषज्ञता का होता है। आज का वैश्विक परिदृश्य केवल इस पर नहीं टिका कि आप 'क्या जानते हैं', बल्कि इस पर है कि आप 'क्या कर सकते हैं'। अब डिग्री के साथ कौशल-आधारित (Skill-based) शिक्षा अनिवार्य हो गई है। आज का युवा अपनी क्षमताओं और डिजिटल साक्षरता से पहचाना जाता है। भीड़ का अनुसरण करने के बजाय अपनी योग्यता और समय की माँग को समझें। चाहे वह विदेशी भाषा सीखना हो, कोडिंग में महारत हासिल करना हो या मैनेजमेंट के गुर- जिस कार्य में आपको आनंद मिलता है, वही निरंतरता अंततः बड़ी सफलता का आधार बनती है।

### किताबों से आगे की दुनिया

छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए यह समय व्यक्तित्व को बहुआयामी बनाने का है। केवल 'रट्टू तोता' बनने के बजाय व्यावहारिक ज्ञान अर्जित करना आज की सबसे बड़ी माँग है। खेलकूद, वाद-विवाद, कोडिंग या सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता (Leadership) विकसित करती है। वर्तमान दौर में 'सॉफ्ट स्किल्स' उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी अकादमिक उपलब्धियाँ। एक अच्छा वक्ता या धैर्यवान टीम लीडर भविष्य के कॉर्पोरेट जगत में कहीं अधिक सफल साबित होता है।

### अपनी पगडंडी खुद बनाएँ

समाज अक्सर सफलता की एक संकीर्ण परिभाषा गढ़ देता है, जो युवाओं को उनकी मौलिकता से दूर ले जाती है। लेकिन आज संभावनाओं के द्वार व्यापक हैं। एक लेखक अपनी कलम से समाज बदल सकता है, एक खिलाड़ी देश का गौरव बन सकता है और एक युवा उद्यमी हजारों के लिए रोजगार पैदा कर सकता है। भेड़चाल से बचें और अपनी राह स्वयं निर्धारित करें। इतिहास साक्षी है कि जिन्होंने लीक से हटकर अपने रास्ते खुद बनाए, वही दुनिया में वास्तविक क्रांति ला पाए हैं।

### गिरने में नहीं, गिरकर न उठने में हार है

इस सफर में असफलता आना स्वाभाविक है, जो वास्तव में एक शिक्षक की भूमिका निभाती है। यदि किसी परीक्षा में परिणाम अपेक्षित न मिले, तो उसे अंत नहीं, बल्कि एक 'री-रूट' के रूप में देखें। हर असफलता सुधार का अवसर देती है। थॉमस एडिसन से लेकर डॉ. कलाम तक, सभी ने अपनी हार को सफलता की सीढ़ी बनाया। यही सकारात्मक दृष्टिकोण आपको भविष्य की बड़ी चुनौतियों के लिए मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाता है।

### आज का निवेश, कल का फल

भविष्य की चिंता में वर्तमान के अवसरों को खो देना समझदारी नहीं है। भविष्य, वर्तमान की नींव पर ही खड़ा होता है। आज की मेहनत, अनुशासन की आदतें और छोटे-छोटे सकारात्मक निर्णय ही कल की सफलता तय करेंगे। समय का प्रबंधन वह कुंजी है, जो प्रगति के बंद दरवाजे खोल देती है। जो व्यक्ति आज अपने समय का मूल्य समझता है, वही कल अपने बड़े सपनों को साकार देख पाता है।

### वैचारिक ऊर्जा से सृजन

सकारात्मक सोच को जीवन का स्थाई हिस्सा बनाएँ। हमारे विचार ही हमारी दिशा और दशा तय करते हैं। आत्मविश्वास वह आंतरिक ऊर्जा है, जो विपरीत परिस्थितियों में टूटने के बजाय निखरने की प्रेरणा देती है। अप्रैल 2026 का यह विजन एक ऐसे सशक्त भारत का है, जहाँ हर युवा आत्मनिर्भर और जिज्ञासु है। अवसरों की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें पहचानने और सही दिशा में साहसपूर्वक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। स्वयं की शक्तियों को पहचानिए और उड़ान भरिए, क्योंकि यह अनंत आसमान सिर्फ आपका इंतजार कर रहा है।

### चलते-चलते यह भी जानियेः नए वित्तीय वर्ष और इसकी अहमियत

भारत में 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष (2026-27) शुरू होता है, जो राष्ट्रीय आर्थिक और व्यक्तिगत प्रगति के लिए नई ऊर्जा का संकेत है।

**युवाओं के लिए अवसरः** बजट में घोषित नई स्कॉलरशिप, शिक्षा ऋण और कौशल विकास (Skill Development) के नए कार्यक्रम इसी महीने से प्रभावी होते हैं। विद्यार्थियों को सरकारी पोर्टल्स पर इन अवसरों को जरूर तलाशना चाहिए।

**वित्तीय अनुशासनः** यह महीना 'बचत और निवेश' का संकल्प लेने का सर्वोत्तम समय है। युवाओं को 'कम्पाउंडिंग' (चक्रवृद्धि) की शक्ति समझनी चाहिए— आज बचाया गया थोड़ा सा धन भविष्य के बड़े लक्ष्यों की आधारशिला बनता है।

**ऐतिहासिक आधारः** अप्रैल से मार्च का यह चक्र हमारे कृषि प्रधान समाज और फसलों की कटाई के व्यावहारिक चक्र से जुड़ा है, जो आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

इस नए वित्तीय वर्ष में केवल अपनी कक्षा के अंक बढ़ाने का लक्ष्य न रखें, बल्कि अपनी 'लर्निंग वैल्यू' और 'फाइनेंशियल समझ' को भी विकसित करें। स्वयं पर किया गया निवेश ही दुनिया का सबसे सुरक्षित और लाभकारी निवेश है।

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25

# स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में सतत् प्रगति पथ पर

# छत्तीसगढ़

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

- विगत दो वर्षों में **1600 से अधिक** चिकित्सकीय पदों पर भर्तियां
- दूरस्थ इलाकों तक सुगम चिकित्सा सेवाओं के लिए **पीएम जनमन योजना** अंतर्गत 57 डेडीकेटेड मोबाइल मेडिकल यूनिट
- टेलीमेडिसिन के माध्यम से विगत दो वर्षों में **2 लाख से अधिक** लोगों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत पिछले दो वर्षों में कुल 31.44 लाख से अधिक क्लेम प्रकरणों में लगभग **₹4551 करोड़** का उपचार/भुगतान
- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत पिछले दो वर्षों में कुल 2273 लाभार्थियों को **₹62.20 करोड़** की उपचार सहायता
- मुख्यमंत्री शासकीय अस्पताल रूपांतरण कोष अंतर्गत विगत दो वर्षों में 177 कार्यों हेतु **₹271.45 करोड़** की प्रशासकीय स्वीकृति
- **5 नए** शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना
- **6 नवीन** शासकीय फिजियोथैरेपी चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना
- **9 नवीन** शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना

R.O. No. : 13711/ 1

सुशासन से समृद्धि की ओर | ChhattisgarhCMO | DPRChhattisgarh | www.dprcg.gov.in


स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।**
*RNI-MPBIL/2011/39805* समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)